newsjankalyanseva@gmail.com

साप्ताहिक

जनकल्याण सेवा

ठाणे | वर्ष - २२ | अंक - ४१ | ३० अक्टूबर से ५ नवंबर २०२३ | पृष्ठ - ४ | कीमत : २ रु. | Postal Reg. No. PLG/08/2022-2024

संपादकीय

संपादक सीमा गुप्ता

शिक्षा के दावे खोखले

शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें तमाम दावे करती रहती हैं। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। पालघर के आदिवासी इलाकों में तो हालात यह है कि बुनियादी सुविधाएं तक स्कूलों से नदारद हैं, जिससे यहां शिक्षा का स्तर सुधरने की बजाय दिन-ब-दिन बिगड़ता ही जा रहा है। कहीं स्कूल है तो शिक्षक ही नहीं हैं और कहीं दोनों ही नहीं हैं। डहाणू के सरावली-मोरपाड़ा इलाके में करीब ५ वर्षों से रेलवे की (डीएफसीसीएल) परियोजना को पूरा करने के लिए जिला परिषद के एक सरकारी स्कूल को तोड़ा गया था, लेकिन स्कूल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया, जिससे इस स्कूल में पढ़नेवाले नौनिहाल भीषण गर्मी में भी कंटेनरों में भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन और रेलवे से स्कूल को बनाने की मांग की है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। दिल्ली और मुंबई के बीच डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर (डीएफसीसीएल) परियोजना के लिए ५ साल पहले स्कूल की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। इसलिए उस स्कूल के बच्चे बीएचसीसीआईएल मुंबई द्वारा निर्मित दो कंटेनरों में पढ़ाई कर रहे हैं। कंटेनरों में चल रहे स्कूल में आनेवाले बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के दिनों में कंटेनर लीक होते हैं और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, इसलिए छात्रों की संख्या कम हो गई है। इससे गरीब छात्रों की पढ़ाई में बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और सरकारी स्कूल टूटने के बाद बन नहीं रहा है। स्कूल के मुख्य शिक्षक कोमल सिंह शेरे ने कहा कि स्कूल में फिलहाल ३२ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल कंटेनर में संचालित करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जल्द से जल्द स्कूल के भवन का निर्माण कराने की मांग की गई है। दो कंटेनरों में पहली से पांचवीं तक चल रहे स्कूल के बच्चों के लिए न पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था है, न ही यहां बिजली का कनेक्शन है, जिससे बच्चों को गर्मियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है, लेकिन फिर भी भवन निर्माण में देरी हो रही है, जिससे इस स्कूल को छोड़कर बच्चे दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं।

वन को उजाड़ कर स्विमिंग पुल बनाने की योजना, पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी

जेकेएस संवाददाता

भायंद : मीरा-भायंदर मनपा प्रशासन द्वारा रामदेव पार्क परिसर के आरक्षण क्रमांक २३० पर मियावाकी पद्धति से वन उगाए गए थे. इस मियावाकी वन के ६०७ बडे.वृक्ष और २६६० छोटे ऐसे कुल ३ हजार २६७ भारतीय प्रजाति के वृक्षों को जड. सहित उखाड. कर अन्यत्र पुनरोपित करने का निर्णय लिया गया है. इस आशय की नोटिस सहायक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी योगेश गुणिजन ने प्रकाशित की है. इस पर सुझाव और आपत्ति के लिए शहर के नागरिकों को ७ दिन की अवधि दी गई है. इस वन को उजाड.कर यहां स्विमिंग पुल का निर्माण किए जाने की योजना है. मनपा प्रशासन का दावा है कि इससे ३ गुना वृक्ष रोपित की जाएगी. जबकि प्रत्यक्ष में मनपा के पास इतनी जगह उपलब्ध नही है. मनपा प्रशासन

के इस निर्णय से पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी देखी जा रही है. भाजपा के १४५ मीरा भायंदर विधानसभा चुनाव प्रमुख एड. रवि व्यास ने मनपा आयुक्त संजय श्रीपतराव काटकर को पत्र लिखकर इन वृक्षों को स्थानांतरित करने की नोटिस रद्द करने की मांग की है. अन्यथा भाजपा द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी है.

वृक्ष काटने या स्थानांतरित करने का निर्णय अन्याय कारक है. इससे जनप्रतिधियों, पर्यावरण प्रेमियों व सामाजिक संस्थाओं में नाराजगी है. इन वृक्षों पर पक्षियों के घोंसले हैं. शहर के मध्य से इस हरित वन को स्थानांतरित करने से पर्यावरण संतुलन बिगडऩे की आशंका है. इसलिए इस वन को उजाडऩे और वृक्षों को स्थानांतरित करने की नोटिस रद्द करें, अन्यथा भाजपा पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर आंदोलन करेगी.

कोरोना संक्रमण काल में खरीदे गए चिकित्सा उपकरणों की निलामी

जेकेएस संवाददाता

भायंदर, मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन ने कोरोना महामारी के संक्रमण काल में बनाए गए अस्थाई कोविड सेंटर को स्थाई रूप से बंद करने और वहां के चिकित्सा उपकरणों को नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया है. बता दें कि मार्च २०२० में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में मरीजों की बढती संख्या और उनके उपचार के लिए अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए मनपा के प्रमोद महाजन, मीनाताई ठाकरे और अप्पा साहेब धर्माधिकारी सभागृहों के इमारत में अस्थाई कोविड सेंटर का निर्माण किया गया था. मरीजों के उपचार के लिए करोडों रुपए के चिकित्सा उपकरण खरीदे गए थे. इन अस्थाई कोविड सेंटरों में हजारों की संख्या में कोरोना मरीजों के उपचार कर उनके जान बचाने में प्रशासन को सफलता मिली थी. धीरे-धीरे कोरोना महामारी पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया और करीब डेढ.वर्षों से कोरोना का प्रभाव खत्म हो चुका हैं, जिससे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड के दौरान लगाए गए सभी कोविड नियमों के प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए हैं, जिससे मनपा के सभागृहों में बनाए गए अस्थाई कोविड सेंटरों को स्थाई रूप से बंद कर उन सभागृहों को नागरिकों के लिए खोलने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया है. प्रशासन द्वारा खरीदें गए चिकित्सा उपकरणों को रखने और रखरखाव के लिए मनपा के पास पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है. साथ ही इन उपकरणों के इस्तेमाल न किए जाने से उनके खराब होने की संभावना है, इसलिए इन्हें बिक्री करने का निर्णय लिया गया है. इन चिकित्सा उपकरणों के बाजार मूल्य जानने हेतु वैधकिय महाविद्यालयों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इनका मूल्यांकन कराया जाएगा और इसके बाद इसे नीलामी के माध्यम से बिक्री की जाएगी.

स्वच्छता अभियान के लिए समितियों का गठन

जेकेएस संवाददाता

भायंदर, मीरा-भायंदर मनपा ने एक विशेष शहर स्वच्छता अभियान शुरू किया है. पहले चरण में १६ से २७ अक्टूबर २०२३ तक सभी शहर में स्वच्छता अभियान चलाया है. इस अभियान में सभी विभागों को अपने-अपने काम में होने वाली त्रुटियों और उसमें किये जाने वाले सुधार के निर्देश दिये गये हैं. निर्देश पर अमल हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी जरूरी है और इसके लिए विशेष स्वच्छता निरीक्षण समिति का गठन आयुक्त संजय काटकर ने किया है. मनपा की आय के स्रोत मजबूत करने व तंत्रज्ञान के उपयोग की जांच, सीवरेज लाइन और प्रक्रिया संयंत्रों की सफाई की जांच और इमारत तथा अन्य सार्वजनिक विकास कार्यों की सफाई की जांच करने के लिए ३ अलग-अलग समितियों का गठन किया है. इन समितियों को अलग-अलग कार्यों और उनकी निगरानी की महत्वपूर्ण

जिम्मेदारी सौंपी गई है. मनपा की आय का मुख्य स्रोत नागरिकों से प्राप्त होने वाला कर (टैक्स) है. कर दाता नागरिकों को घर बैठे 'कर भुगतान' की सुविधा को सरल बनाने के लिए मोबाइल एप और अन्य साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समिति गठित की गई है, जिसमें अध्यक्ष मनपा के मुख्य लेखा परीक्षक सुधीर नाकडी. उपायुक्त रवि पवार, शहर अभियंता दीपक खांबित, सिस्टम प्रोग्रामर मनस्वी म्हात्रे को सदस्य और मुख्यलेखा अधिकारी कालिदास जाधव को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इन्हें मनपा को प्राप्त होने वाली निधि, आज तक हुई वसूली और बकाया राशि की जांच, कर भुगतान को सरल बनाने हेतु संगणक प्रणाली की उपयोगिता तथा एक मोबाइल एप के माध्यम से नागरिकों को कर भुगतान की सुविधा के लिए नई संगणक प्रणाली तैयार करने आदि की जिम्मेदारी दी गई है. मलनि:सारण वाहिनी व प्रक्रिया प्रकल्प की स्वच्छता के लिए गठित जांच समिति में अध्यक्ष उपायुक्त मारुति गायकवाड, उप अभियंता शरद नानेगांवकर, विलास गीते को सदस्य और दिनेश कानगुडे को सचिव नियुक्त किया गया है. इस समिति पर मलनि:सारण वाहिनी व प्रक्रिया के बाद बचे पानी की बिक्री, स्वच्छता और सुशोभीकरण, कचरा कुंडी, रोड-गटर की साफ सफाई, केंद्र कार्यान्वित होने की निगरानी करने आदि की जिम्मेदारी है. सभी तीनों समिति को अपनी रिपोर्ट १० नवंबर तक मनपा आयुक्त को सौंपना अनिवार्य होने के आदेश दिए गए हैं.

ड्रग्स की फैक्टरी पर पुलिस का छापा, आरोपी पहुंचे हवालात

मीरारोड: मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के तहत लोकल क्राइम ब्रांच की यूनिट -१ ने बडी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स का कारोवार करने वाले ७ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने १९ किलो एमडी जन्त किया है, जिसकी बाजार में ३७ करोड.रुपये कीमत है। एपीआई अविराज कुराडे ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है।

पुलिस के अनुसार, १८ अक्टूबर को क्राइम ब्रांच ने भाईंदर के विन्यासा लॉजिंग से २५१ ग्राम एमडी (ड्रग्स) के साथ भरत सालेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुवे और शाहनवाज सेवा को गिरफ्तार किया था। इनके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, एक मैगजीन, २ जिंदा कारतूस और वजन करने वाली मशीन

जब्त की थी। आरोपी वजन करने वाली मशीन से एमडी के छोटे-छोटे (१-२ ग्राम) के पैकेट बनाते थे। चारों से पूछताछ के दौरान पुलिस तनवीर अहमद, गौतम घोष और समीर पिंजार तक पहुंची। पालघर में थी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री डीसीपी अविनाश अंबुरे ने बताया कि आरोपी समीर ने पालघर जिले के मोखाडा में ड्रग्स बनाने की अत्याधुनिक फैक्ट्री बनाई थी। फैक्ट्री से पुलिस ने १९ किलो एमडी जब्त किया। इसके अलावा, करोडों का ड्रग्स बनाने का सामान भी पुलिस के हाथ लगा है। समीर कम पढा-लिखा है और इससे पहले हैदरावाद में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। लॉज में कई दिन से ठहरे थे आरोपी भाईंदर के वीपी रोड के जिस लॉज से चार आरोपियों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है, वह बीजेपी के पूर्व नगरसेवक यशवंत कागने का है। सूत्रों का कहना कि आरोपियों ने इस लॉज को ड्रग्स के डिस्ट्रीव्यूशन का अड्डा बना रखा था। वे यहां से ड्रग्स के छोटे-छोटे पैकेट बनाकर वेचा करते थे। लॉज से सटकर एक स्कूल भी है। आरोपी इस लॉज में काफी दिनों से ठहरे हुए थे। यशवंत ने लॉज से अपने संबंध होने से इनकार किया है।

कचरा को नियंत्रण करने के लिए मनपा ने किया सॉफ्टवेयर तैयार

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : राज्य एवं देश में मीरा - भायंदर शहर हरित और स्वच्छ शहर के रूप में पहचाना जाए। इसके लिए मनपा आयुक्त संजय श्रीपतराव काटकर के मार्गदर्शन में मनपा अधिकारियों ,कर्मचारियों और शहरवासियों के सहभागिता से संपूर्ण शहर में विगत १० दिनों से स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है। गुरुवार २६ अक्टूबर को स्वच्छता के लिए मनपा प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य, प्रयास और जनजागरुक हेतु स्व.लता मंगेशकर नाट्य गृह में पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। जिसमें मनपा आयुक्त काटकर ने बताया कि कचरे का निर्माण घरों से होता है, इसलिए कचरे के वर्गीकरण के लिए पहले घरों से ही शुरुआत की जानी चाहिए। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। जिसे प्रायोगिक तौर पर शहर के करीब २०० सोसायटियों में शुरू की गई है। जिसके तहत सोसायटी के

प्रत्येक फ्लैट के दरवाजे पर एक क्यू-आर कोड की स्टिकर चिपकाई गई है। जिसके माध्यम से सफाई कर्मी को यह पता करना है की किस घर से कचरा वर्गीकृत करके दी गई है अथवा किस घर से कचरा वर्गीकृत नही करके दी गई है। कचरा वर्गीकृत नही होने पर कचरा डब्बे का फोटो निकाल कर सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। इस प्रकार से इसकी जानकारी सोसायटी कार्यालय और स्वच्छता निरीक्षक तक पहुंचेगी, और कचरा का वर्गीकरण घरों से ही शुरू करने की जनजागरुकता को बल मिलेगी। इस अवसर पर दीप ज्योति और एन .एच.स्कूल के विद्यार्थियों के साथ मनपा आयुक्त संजय काटकर, डी.बी रियाल्टी के राजीव अग्रवाल सहित उपस्थित मनपा के अधिकारियों -कर्मचारियों ने न कचरा फेकुंगा ,न कचरा फेंकने दूंगा की शपथ लेकर शहर के स्वच्छता का संकल्प लिया। १६ अक्टूबर से शुरू की गई स्वच्छता मुहिम अंतर्गत २६ अक्टूबर तक के १० दिनों में ३५० टन कचरा जमा किया गया, ३०४ किलो प्लास्टिक जप्त की गई और ७ लाख रुपए से अधिक दंड वसूल किए गए। इस विशेष सफाई अभियान में सडक़ें, डिवाइडर, फुटपाथ, चैंबर के ढक्कन, छोटी मरम्मत, गड्ढे भरना, पार्कों से कचरा जमा, मुख्य सडक़ों पर पेडों की छंटाई, सडक़ डिवाइडरों से घास-झाडिय़ों को हटाना, छंटाई, फव्वारों की मरम्मत, चल रहे कार्यों की बैरिकेडिंग करना आदि शामिल थे। मनपा द्वारा, मलबा उठाना, निर्माणाधीन इमारतों में हरित जाल लगाना अनिवार्य करना, धूल पर नियंत्रण, फुटपाथों से बाधक बोर्डों और सामग्रियों को हटाना, खाद्य विक्रेताओं द्वारा फुटपाथ या सडक़ पर फेंके जाने वाले कचरे और पानी पर प्रतिबंध लगाना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान घाट, शौचालय, नालियां, खुली जगहों की सफाई पर जोर दिया गया। इसी तरह, बस स्टेशनों और अन्य स्थानों से स्टिकर पोस्टर हटाने, अनधिकृत बैनर हटाने, मूर्तियों और स्मारकों, किलों, समुद्र तटों, ऐतिहासिक इमारतों की सफाई की गई। भविष्य में अधिक से अधिक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्कूलों, कॉलेजों, एनएसएस, छात्र संघों को शामिल कर शहर की स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार के लिए विशेष प्रयास किये जाने की जानकारी आयुक्त काटकर ने दी।

नालासोपारा में हुई हत्या की शिनाख्त

जेकेएस संवाददाता

नालासोपारा, तुलिंज पुलिस स्टेशन में शाम को रोज की तरह चहल-पहल थी, तभी वायरलेस पर एक मैसेज आया। श्रीरामनगर में एक ओवर ब्रिज के पास, नाले में नायलॉन के बैग में एक लाश होने की सूचना मिली। पुलिस ने घटना-स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शव पर पड़े हुए कपड़े उतारे गए, तो शर्ट के कॉलर में टेलर का नाम और पता लिखा था। चूंकि कॉलर में पिन कोड भी था, इसलिए जांच टीम को संबंधित टेलर की कमाठीपुरा वाली दुकान को ढूंढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। टेलर को शर्ट के आगे और पीछे की तस्वीरें दिखाई गईं। टेलर ने गौर से शर्ट को देखा, तो कॉलर के आगे साइड के नीचे के तीन बटन अलग से दिखे। इन बटनों के बीच का एक बटन टूटा हुआ था। इन सभी बटनों को देखते ही उसके मुंह से अपने आप नाम निकल पड़ा, कृष्णा। उसने बताया कि वह पूरा नाम नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता है कि यह शख्स शर्ट के तमाम बटनों के बीच कॉलर के नीचे वाले तीन-चार बटन हमेशा अलग कलर के लगवाता है। उसने यह भी बताया कि कृष्णा, मुंबई सेंट्रल में किसी मुस्लिम होटल मालिक के यहां काम करता है। जांच टीम कुछ मिनट बाद वहां पहुंची और होटल मालिक को कृष्णा की लाश की फोटो दिखा दी। होटल मालिक ने उसे पहचान लिया और बताया कि

कृष्णा चार दिन से होटल आया ही नहीं। उसके साथ भायंदर में रहनेवाला एक अन्य होटल कर्मचारी भी चार दिन से नहीं आ रहा। पुलिस का शक फिर इस दूसरे कर्मचारी पर चला गया। होटल मालिक के पास कृष्णा का पता नहीं था, लेकिन भायंदर वाले कर्मचारी का था। जांच टीम पहुंच गई उस कर्मचारी के पास और चार दिन से होटल न जाने की वजह पूछी। उसने बहुत सहज जवाब दिया कि बीमार हूं, इसलिए ड्यूटी पर नहीं जा रहा। तब उससे कृष्णा के बारे में सवाल पूछे गए। उसने बताया कि कृष्णा, नालासोपारा में किसी अंकिता (बदला नाम) के साथ रहता है, लेकिन उसे उसका पूरा पता नहीं मालूम। इस कर्मचारी के पास कृष्णा का मोबाइल नंबर जरूर था। जांच टीम ने जब इस नंबर का सीडीआर निकाला, तो उसमें कई नंबर महाराष्ट्र के बाहर के मिले। दो-तीन नंबर मुंबई और नालासोपारा के भी थे। नालासोपारा का नंबर एक महिला का था, जो तुलिंज इलाके की प्रगति नगर बिल्डिंग में रहती थी। जब इस महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उसने साफ कहा कि वह किसी कृष्णा को नहीं जानती। उसने सबूत के तौर पर पुलिस को अपना मोबाइल सेट ही दे दिया कि आप लोग खुद चेक कर लो कि क्या उसमें कृष्णा को कभी कोई कॉल दिख रहा है? जब पुलिस नाइक किरण म्हात्रे ने इस महिला के सामने सीडीआर की डिटेल रख दी, जिसमें उसका कुछ दिन पहले का नंबर दिख रहा था, तो महिला को एकाएक याद आया कि कुछ दिन पहले अंकिता (बदला नाम) ने उससे किसी अर्जेंट कॉल करने के बहाने मोबाइल लिया था। जांच टीम जब ऊपर फ्लैट में पहुंची, तो वह बंद था। फौरन फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाने पर घर एकदम साफ मिला। प्रगति नगर की महिला ने सीसीटीवी में आई महिला की शिनाख्त अंकिता (बदला नाम) के रूप में कर दी। लेकिन, जांच टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि युवती इस वक्त है कहां? प्रगतिनगर वाली महिला के पास संयोग से उसका नंबर था। उस नंबर के सीडीआर में किसी मुख्तार का नंबर मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई।

व्यवसाय को ऊंचाई प्रदान करने मॉड्यूल की स्थापना

भायंदर, व्यवसाय को नई ऊंचाई प्रदान करने के उद्देश्य से एसएसके भारत बीबीआई मीरा भायंदर मॉड्यूल की स्थापना की गई है. भायंदर पश्चिम में मीरा भायंदर मॉड्यूल के उद्घाटन अवसर पर बीबीआई के संस्थापक कार्तिक रावल ने कहा कि उन हजारों साथी उद्यमियों से जुडें, जो संबंध बनाने और अपनी व्यावसायिक चुनौतियों को साझा करके एक-दूसरे की मदद करने के लिए उत्सुक हैं. जैसे ही आप एसएसके भारत बीबीआई का हिस्सा बन जाते हैं, आपको अन्य सदस्यों से रेफरल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे

आपके व्यवसाय के मूल्यवान नेटवर्क का विस्तार होगा. मीरा भायंदर के मॉड्यूल निदेशक सूरज नांदोला ने बताया कि एसएसके भारत बीबीआई व्यवसायों को समर्थन और बढावा देने के लिए आदर्श मंच है, जो उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन व व्यवसाय को बढाने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क के सदस्यों से जुडें.और सहयोग तलाशें व अपने कारोबार को नई ऊंचाई प्रदान करें. इस अवसर पर निदेशक श्याम शंकर उपाध्याय, सीईओ गौरांग ईनामदार आदि कई गणमान्य व्यापार उपस्थित थे.

भाईंदर में माता-पिता वंदना कार्यक्रम संपन्न

भायंदर : माता-पिता की सेवा एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण धर्म है. वे हमारे जीवन के प्रति अपना बलिदान करते हैं. माता-पिता हमारे पहले शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं, और उनका स्नेह और साथ हमें जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में आगे बढ़ने में मदद करता है. उक्त विचार स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. लीला अग्रवाल ने व्यक्त किए. वे युथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन (युथ फोरम) द्वारा भायंदर पश्चिम के सालासर कॉम्प्लेक्स में आयोजित मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम में बोल रही थी. उन्होंने कहा कि माता-पिता हमारी पहचान और आत्म समर्पण का प्रतीक होते हैं. उनकी सेवा और प्रेम के बिना, हम अपने जीवन का सार्थक और सफल मार्ग नहीं चुन सकते. कार्यक्रम की अतिथि विशेष पूर्व नगरसेविका रीटा शाह ने कहा कि वे हमें नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण सीख देते हैं. उक्त अवसर पर टीवी कलाकार तशीन शाह ने कहा कि माता-पिता की सेवा करना हमारा धर्म है. हमें उनकी आयु और स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखना चाहिए. वे हमारे जीवन के अधिकांश समय काम करके हमें सफलता पाने का मौका देते हैं और हमें उनका साथ देने का आदर और प्रेम देना हमारी जिम्मेदारी होती है, इसलिए, हमें माता-पिता की सेवा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए. फोरम के अध्यक्ष दीपक जैन ने डॉ. उदय मोदी द्वारा निर्मित होने वाले मां बाप मंदिर इमारत में दानदाताओं से दान की अपील की. श्रवण टिफिन सेवा के डॉ. मोदी ने कहा कि वृद्धाश्रम भारत की संस्कृति नहीं हैं. भावना जैन ने स्वस्थ रहने की टिप्स दी.

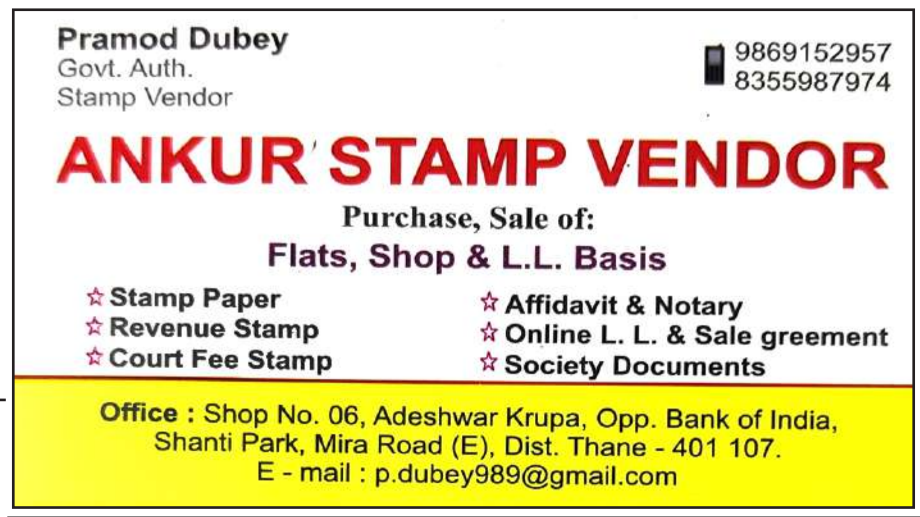

भाईंदर में दिव्यांगों ने किया कला का प्रदर्शन

भायंदर, मारवाडी जनकल्याण परिषद द्वारा इस बार दशहरे के शुभ अवसर पर दिव्यांग कलाकारों के गीत-संगीत के अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में सैंकडों लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया गया, ताकि वे दशहरा व दीपावली आदि त्योहार अच्छे ढंग से मना सकें. इस अवसर पर ५ जरूरतमंद महिलाओं को सीए रितेश बुरड.के सौजन्य से सिलाई मशीनों का वितरण किया गया और एक बुजुर्ग को वॉकिंग स्टिक दी गई. साथ ही उनके स्वरुचि भोजन की व्यवस्था भी की गई. उक्त कार्यक्रम में दिव्यांगो द्वारा गीत-संगीत की शानदार प्रस्तुति की गई. उपस्थित जनसमुदाय ने दिव्यांगों द्वारा प्रस्तुत गीत-संगीत की भरपूर आनंद लिया. कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन वरिष्ट समाजसेवी किशन लाल मोर, शरद गोयनका, पूर्व नगरसेविका शानू गोहिल और संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया गया.

सीमेंट - कंक्रीट की होगी सड़के, गड्ढों से मिलेगा छुटकारा

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : एमएमआरडीए और एमबीएमसी द्वारा १८०० करोड.रुपए खर्च कर मीरा भायंदर की सडक़ों को सीमेंट और कंक्रीट की बनाई जाएगी। जिसमें एमएमआरडीए १४०० करोड.रुपए और एमबीएमसी ४०० करोड. रुपए खर्चा करेगी। जिसके कार्य की शुरूआत आगामी सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। इस कार्य का कार्यादेश ठेकेदार को दे दी गई है। २५ वर्षों तक यह सडक़े सुव्यवस्थित और मजबूत रहे, इस तरह से कार्य किया जाएगा। मीरा - भायंदर की ८० प्रतिशत सडक़ें सीमेंट और कंक्रीट की बनाई जाएगी।यह

कार्य मार्च २०२५ तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ऐसी जानकारी विधायक प्रताप सरनाईक ने दी है। सरनाईक ने बताया कि मीरा भायंदर शहर के लिए विकास के लिए राज्य सरकार ने करीब ३००० करोड.रुपए दिए हैं। कुछ विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों की अनुमति प्राप्त करना बाकी है। उन कार्यों की समीक्षा के लिए सरनाईक ने मनपा आयुक्त -प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर से मुलाकात की। साथ ही सभी विकास के कार्य समय से पूर्ण हो और राज्य सरकार से प्राप्त निधी का समुचित सदुपयोग हो और सीमेंट कंक्रीट की सडक़े बनाने से पूर्व सूर्या प्रकल्प से होने वाली पानी आपूर्ति के वितरण के लिए शहर के अंतर्गत जलवाहिनी बिछाने का कार्य पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जिससे जलवाहिनी बिछाने के लिए सडक़ों को पुन: नही खोदा जाए। शहर विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक में आयुक्त काटकर ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया। राज्य सरकार से विकास कार्यों के लिए जिस प्रकल्प के लिए निधी आई है,उनमें से कुछ कार्यों की टेक्निकल बातें पूर्ण करना बाकी है।विभिन्न विभागों की अनुमति प्राप्त कर आगामी एक वर्ष में विकास कार्यों के लोकार्पण करने आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा संपन्न हुई।

पुलिसकर्मी से रिश्वत ले रहा सरकारी वकील चढ़ा एसीबी के हत्थे

पालघर : पालघर में एक पुलिसकर्मी से रिश्वत ले रहे सरकारी वकील को एसीबी ने दबोच लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिसकर्मी के विरुद्ध तारापुर पुलिस स्टेशन में साल २०१५ में भारतीय दंड सहित की धारा ३७६ के तहत मामला दर्ज किया गया था। जून २०२३ में अदालत ने पुलिसकर्मी को आरोपों से बरी कर दिया था। पुलिसकर्मी ने पालघर जिला पुलिस बल में पदोन्नति के लिए आवेदन किया था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने अतिरिक्त लोक अभियोजक (सरकारी वकील) पालघर को पत्र लिखकर बरी करने पर रिपोर्ट मांगी थी। उस

रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देने के लिए अपर लोक अभियोजक ने १० हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। मामला ७ हजार में तय होने के बाद पुलिसकर्मी ने मामले की शिकायत एसीबी से कर दी। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर ७ हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों सरकारी वकील सुनील सावंत को पकड़ लिया। सावंत करीब ७ वर्षों से पालघर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्ग १ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

मनपा स्कूलों की मनमानी, प्रश्नपत्रिका की यही कहानी ! :परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र से छात्र वंचित

मुंबई : मुंबई मनपा पर प्रशासक नियुक्त होने के बाद से मनपा स्कूलों की हालत बदतर हो गई है। इस बीच मनपा के हिंदी माध्यम स्कूलों की परीक्षा शुरू होते ही अब छात्रों को प्रश्नपत्र से वंचित रखे जाने का मामला सामने आया है। बुधवार को मुंबई के कई भागों में भूगोल की परीक्षा के दौरान ५० में २० छात्रों को प्रश्नपत्र से काम चलाना पड़ा तो कहीं प्रश्न पत्र ही न पहुंचने की जानकारी सूत्रों से मिली है। इसके कारण शिक्षक सहित अभिभावकों द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है। मुंबई में मनपा के लगभग १,१०० स्कूल हैं, जिनमें चार लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं।

इन स्कूलों में पिछले कुछ दिनों से छमाही परीक्षा शुरू हो गई हैं, लेकिन छात्र प्रश्नपत्र की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बुधवार को कुछ स्कूलों में भूगोल की परीक्षा थी, लेकिन छात्रों को प्रश्नपत्र की समस्या का सामना करना पड़ा है। सूत्रों की मानें तो सायन के आस-पास के कुछ स्कूलों में यह समस्या अधिक देखने को मिली है। इसकी सूचना विभाग को दिए जाने के बावजूद इस समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ है। सूत्रों की मानें तो मनपा शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश सभी स्कूलों के हेडमास्टर को दिया गया है, जिसके बाद कुछ स्कूलों में हेडमास्टर द्वारा खुद पेपर बनाकर प्रिंट कराने की बात कही गई है, लेकिन प्रिंट कराने के लिए पैसे नहीं दिए जाने के कारण प्रश्नपत्र की समस्या का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। कुछ स्कूलों में तो प्रश्नपत्र बोर्ड पर लिखकर छात्रों को इससे ही हल करने की बात कही जा रही है। सिर्फ आठवीं और ९वीं के छात्रों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मनपा शिक्षा अधिकारी राजेश कंकाल ने बताया कि किसी भी स्कूल में प्रश्नपत्र कमी की जानकारी हमारे पास नहीं है। प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हेडमास्टर की है, लेकिन इस तरह किसी स्कूल में हो रहा होगा तो कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल वैन का ड्रायवर छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार

जेकेएस संवाददाता

मुंबई : चेंबूर इलाके में एक स्कूल वैन ड्राइवर ने कार में अकेली छात्रा को अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ छेडछाड़ की। छात्रा की मां की शिकायत के आधार पर तिलकनगर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना १९ अक्टूबर को चेंबूर के तिलकनगर इलाके में हुई थी। पीडिता ११ साल की लडक़ी एक स्थानीय स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढती है। १९ अक्टूबर को स्कूल से घर लौटते समय वह स्कूल वैन में अकेली थी। मौका पाकर आरोपी तुषार भालेराव ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस इलाके में वैन खडी की और लडक़ी को मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़खानी की। बच्ची चिल्लाई तो आरोपी ने उसे धमकाया और उसके घर के पास छोड़ दिया। इसके बाद पीडिता काफी डर गई। मां के पूछने पर भी बच्ची कुछ बताने के मूड में नहीं थी। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे भरोसे में लेकर बात किया, तो उसने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। इस संबंध में उसकी मां द्वारा बुधवार को तिलकनगर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

जेतवन बुद्ध विहार में वर्षावास का समापन समारोह

मुंबई : कांदिवली पूर्व जेतवन बुद्ध विहार में 'वर्षावास का समापन समारोह। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजभूषण वसंत कांबले, प्रवक्ता रिपब्लिकन सेना महाराष्ट्र राज्य ने की। उस समय डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का मानवता का धम्म, शांति निर्माता भगवान बुद्ध ने भारतीयों को और देश में आज की स्थिति, अंबेडकरवाद और संविधान और वर्तमान स्थिति में बदलती दिशा, लोकतंत्र के नाम पर संविधान की समाप्ति, संविधान और वर्तमान को नष्ठ करने वाले शासकों और अंबेडकर समूह की जिम्मेदारी और कर्तव्य डॉ. भारत रत्न को रोककर देश में लोकतंत्र और संविधान का युग। समाजभूषण वसंत कांबले ने

सरसेनानी आदरणीय आनंदराज अंबेडकर साहब द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के बताए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाज भूषण काकासाहेब खंबालकर अध्यक्ष रिपब्लिकन सेना महाराष्ट्र राज्य के नेतृत्व में निकाली गई संविधान बचाव यात्रा पर विस्तृत विचार दिए। सचिव एवं संयोजक सुनील भालेराव एवं समस्त सहकारी समितियां एवं महिला मंडल.मुंबई द्वारा आयोजित कोषाध्यक्ष आनंद लावले आदि.

सेवानिवृत्त अधिकारी के घर पर मारा था छापा, ३५ लाख रुपए लेकर फरार होनेवाले चढ़े पुलिस के हत्थे

जेकेएस संवाददाता

मुंबई : बॉलीवुड मूवी स्पेशल २६ की तर्ज पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) अधिकारी बनकर फिल्म सिटी में कारोबारी और सरकारी अधिकारियों के घर छापेमारी कर उन्हें लूटनेवाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सहित १२ लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, तीन महीने पहले नई मुंबई में एक सेवानिवृत सरकारी अधिकारी के घर कुछ लोग अपने आप को भ्रष्ठाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का अधिकारी बता कर छह लोग छापेमारी करने पहुंचे थे। घर में घुसने के बाद इन शातिर लुटेरों ने करीब ३५ लाख रुपए नकद और

कीमती सामानों को लेकर रफूचक्कर हो गए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने गैंग के ११ लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया था। विरार पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र कांबले ने बताया कि नई मुंबई के एरोली में स्थित लोक निर्माण विभाग के एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के घर २१ जुलाई को इस गैंग के ६ लुटेरों ने एसीबी अधिकारी बनकर छापेमारी की। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और कीमती सामानों को एक जगह एकत्रित करते रहे। बाद में यहां से ३४.८५ लाख रुपए नकद और कीमती सामानों को जब्त करने के नाम पर लेकर वे चंपत हो गए। विरोध करने पर आरोपियों ने सरकारी अधिकारी की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। लुटेरों के चले जाने के बाद सरकारी अधिकारी को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने डकैती, आपराधिक साजिश, धमकी और सरकारी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने जैसे अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्जकर जांच शुरू की। राजेंद्र कांबले ने बताया है कि गैंग से जुड़े ११ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इनसे पूछताछ के बाद गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही थी, जिसकी पहचान ३५ साल के अमित बारीक के तौर पर हुई थी। हाल ही में नई मुंबई पुलिस को सूचना मिली थी कि बारीक, विरार के चंदनसर में मौजूद है। इसके बाद विरार पुलिस की मदद से उसे घेर कर दबोच लिया गया। २२ अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी हुई। इन सभी से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस तरह से उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी बनकर कितने लोगों के घर छापेमारी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है।

न्यू मलाबार हिल जलाशय योजना में भ्रष्ठाचार ! जलाशय को लेकर मनपा और जनता आमने-सामने

जेकेएस संवाददाता

मुंबई : मलाबार हिल जलाशय इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे तोड़कर नए सिरे से बनाना है या इसकी मरम्मत करनी है, इस पर जनता और सरकार आमने सामने आ गई है। सरकार की अगुवाई में काम करने वाली मनपा इस जलाशय को तोड़कर नए सिरे से न्यू मलाबार हिल जलाशय बनाना चाहती है, लेकिन जनता इसके खिलाफ है। अब इस मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। तीन इंजीनियरों ने इसे तोड़कर नया बनाने की योजना में भ्रष्ठाचार होने का अंदेशा जताया है। उनका कहना है कि इसे तोड़कर नया बनाने में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्ठाचार हो सकता है। इस संदर्भ में उन इंजीनियरों ने मनपा आयुक्त को पत्र भी लिखा है। मनपा सूत्रों के अनुसार, जलाशय के पुनर्निर्माण पर लगभग ६९८.५ करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है। प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर शिरीष पटेल, सिविल इंजीनियर अल्पा शेठ और डॉ. वासुदेव वी नोरी ने मलाबार हिल जलाशय पुनर्निर्माण पर चिंता जताते हुए मनपा प्रमुख आईएस चहल को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मौजूदा जलाशय की मरम्मत का निर्णय लिया गया है। लेकिन कुछ साल पहले हमने इस जलाशय को करीब से देखा था और यह अच्छी अवस्था में था। इंजीनियरों ने आगे लिखा है कि इस जलाशय का स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं हैं कि इसे तोड़ा जाए और नया बनाया जाए। इसकी संरचना इतनी तेजी से खराब नहीं हो सकती है। उन लोगों ने कहा कि जलाशय की मरम्मत से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं लग रहा है। इंजीनियरों ने आरोप लगाया कि इसकी जल स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जलापूर्ति के लिए बेहतर पाइपलाइन होना जरूरी है।

मिरा भाईंदर में दिव्यांगों के लिए उठी आवाज

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : मीरा भायंदर मनपा क्षेत्र के दिव्यांगों को केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सुविधा का लाभ उठाने तथा परवाना के लिए अलग -अलग ३ विभागों के चक्कर लगाने पडते हैं। भायंदर पश्चिम में मैक्सस मॉल के पास स्थित दिव्यांगों के सेवा लिए उपलब्ध कार्यालय पहली मंजिल पर है। जहां दिव्यांगों को पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। इस कार्यालय को तल मंजिल पर स्थानांतरित करने की मांग ११ जनवरी २०२१ से समाज कल्याण अधिकारी, मनपा के समाज कल्याण विभाग से की जा रही है, लेकिन अब तक इस कार्यालय को तल मंजिल पर स्थानांतरित नहीं की गई। दिव्यांगों के अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष करने वाली संस्था भावना फाउंडेशन की भावना तिवाडी ने मनपा आयुक्त -प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर को दिव्यांगो के लिए मनपा मुख्यालय में ही एक खिडक़ी योजना जैसी सुविधा देने की लिखित मांग की है। जिससे दिव्यांग लोगों को अपने कार्य के लिए तीन अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पडे.। साथ ही फाउंडेशन की अध्यक्षा तिवाडी ने शहर में दिव्यांगो के उदार निर्वाह हेतु सडक़ो के किनारे गटर पर स्टॉल लगाने की अनुमति के संदर्भ में आयुक्त काटकर को अवगत कराया। वर्ष २०१४ से मनपा ने दिव्यांगो को स्टॉल की अनुमति देना बंद कर दिया है, लेकिन तिवाडी का आरोप है कि आर्थिक व्यवहार कर, राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों को स्टॉल के परमिशन दिए जा रहे हैं, और मजबूर असहाय दिव्यांगो को उनके उदर निर्वाह हेतु स्टॉल की अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि इसके लिए दिव्यांगो ने कई बार इसकी लिखित शिकायत, मोर्चा, आंदोलन किए ।फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भावना फाउंडेशन ने मांग की है की ठाणे और मुंबई मनपा की तरह अपंग ,दिव्यांग लोगों को उदर निर्वाह हेतु स्टॉल के अनुमति देना शुरू करें, जिससे उन्हें भी रोजगार मिले और समाज में सम्मान के साथ जिंदगी बिता सकें। मनपा आयुक्त काटकर ने फाउंडेशन की मांग पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए, दिव्यांगो के लिए मनपा मुख्यालय में ही सभी कार्यालय स्थानांतरित करने, अवैध स्टॉल पर कारवाई करने तथा दिव्यांगों के स्टॉल के लिए अनुमति देने संबंधी निर्णय शीघ्र लेने का आश्वासन दिया है।

एमबीएमसी के ४ स्कूलों में ९वीं १० वीं कक्षा की अनुमति

भायंदर. मीरा-भायंदर मनपा के ४ स्कूलों में ९वीं और १०वीं कक्षा शुरू करने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है. मीरा- भायंदर मनपा की कुल ३६ स्कूल है, जिसमें प्राथमिक ८वीं तक की शिक्षा दी जाती है, जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा होती थी. इसको ध्यान में रखते हुए मीरा-भायंदर मनपा स्कूलों में ९वीं और १०वीं की कक्षा शुरू करने की मांग तत्कालीन महापौर ज्योत्सना हसनाले ने राज्य सरकार से की थी. मनपा की मांग पर संज्ञान लेते हुए ९ अक्टूबर २०२३ को राज्य सरकार के कार्यासिन अधिकारी विवेक सपकाल ने शासन आदेश जारी कर मनपा को उच्च माध्यमिक शिक्षण का दर्जा प्रदान कर दिया है, जिससे अब ९वीं और १०वीं की कक्षा भी मनपा स्कूलों में शुरू की जा सकेगी.

मामुली विवाद के चलते फेरीवाले और दुकानदार में मारपीट

भायंदर। मीरा भायंदर में अवैध फेरीवालों की दबंगई से न सिर्फ राहगीर,बल्कि दुकानदार भी तंग हैं।फुटपाथ और सडक़ पर कब्जा जमाए फेरीवालों ने रविवार रात में मामूली सी बात पर मीरा रोड में जमकर तांडव मचाया। २०-२५ फेरीवालों के झुंड ने दुकान से खींचकर दुकानदार और उसके नौकर को लात घूसों से बुरी तरह पीट दिया।घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।खबर लिखे जाने तक तीन फेरीवालों को गिरफ्तार किया जा चुका था। मीरा रोड, शांति नगर के गणेश चौक पर गंगासिंह राजपुरोहित की महेरिया नाम की इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप है।शॉप के बाद पार्क की गई गाडी निकालते समय फेरीवाले वाले की बाइक से दुकानदार की बुलेट की सीट फट गई। इस बात को लेकर पहले कहासुनी और फिर विवाद हो गया।आरोप है कि २०-२५ की झुंड में फेरीवाले गंगासिंह की दुकान में घुस आए।पहले उन्हें और फिर उनके नौकर करण राजपुरोहित को खींचकर बुरी तरह पीट दिये।इस दौरान फेरीवालों के झुंड ने जमकर बवाल काटा।डर के मारे व्यापारी दुकानें बंद कर भाग खडे हुए।वाकया रात्रि लगभग ११ बजे का है।रात्रि दो बजे विधायक गीता जैन व्यापारियों को लेकर थाने पहुंची। नया नगर पुलिस थाने के पीआई विलास सूपे ने कहा कि मामले में चार नामजद सहित २०-२५ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबर लिखे जाने तक अनान मोहमद सुथार,मोहमद शोएब मोहम्मद अल्ताफ शेख तथा अजहर हैदर अली शेख को गिरफ्तार कर लिया गया था।उधर रविवार को सुबह विधायक गीता जैन तथा पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता व्यापारियों को लेकर गणेश चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनकी मांग थी की गणेश चौक अवैध फेरीवालों और उनकी गुंडागर्दी से मुक्त कराया जाए।मौके पर मीरा भायंदर मनपा आयुक्त संजय काटकर को आना पडा।उन्होंने २ दिन के भीतर नतीजापूर्ण कार्रवाई का भरोसा दिया है। बता दें कि शांति नगर,सेक्टर १,२,३,४ में फेरीवाले सडक़ और फुटपाथ पर कब्जा कर रखे हैं।आलम यह रहता है कि दुकान नजर ही नहीं आती है।शाम को गाडी से चलना तो दूर पैदल भी आप निकल नहीं सकते हैं।फेरीवालों को संरक्षण देने का आरोप व्यापारियों ने स्थानीय नगरसेवकों पर लगाया है।उनका आरोप है कि नगरसेवक हफ्ते के रूप में मोटी रकम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देते हैं।ज्यादातर फेरीवाले मीरा भायंदर के बाहर से हैं।

आपले सरकार निवारण से मीरा भाईंदर का नाम गायब

जेकेएस संवाददाता

भायंदर, . राज्य सरकार के 'आपले सरकार' शिकायत निवारण पोर्टल से अचानक मीरा-भायंदर महानगरपालिका और मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय का नाम हटा दिया गया है. इस पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है. स्थानीय विधायक गीता भरत जैन ने राज्य सामान्य प्रशासन विभाग के अपार मुख्य सचिव को 'पोर्टल' में पुन: दोनों नाम समाविष्ठ करने का आग्रह लिखित निवेदन के माध्यम से किया है. अक्टूबर २०१७ में 'आपले सरकार शिकायत निवारण पोर्टल' शुरू किया था, जिसमें आम नागरिकों को मनपा पुलिस, जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर मंत्रालय के प्रत्येक विभागों तक शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. इस पोर्टल पर नागरिकों के दर्ज शिकायतों पर अधिकतम २१ दिन के भीतर शिकायत का निवारण कर, शिकायतकर्ता को उत्तर देना अनिवार्य था. इस वेबसाइट को अपडेट किया गया था, पर अपडेट किए जाने के बाद से ही 'आपले सरकार शिकायत निवारण पोर्टल' से मीरा-भायंदर व मीरा-भायंदर-वसई- का नाम गायब हो गया है.

डीपी प्लान में फेरबदल का सुझाव

जेकेएस संवाददाता

भायंदर. मीरा भायंदर शहर के संशोधित नए विकास योजना प्रारूप (डेवलपमेंट प्लान) को महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ की कलम २८ (४) के अनुसार बुधवार को आम नागरिकों के अवलोकनार्थ प्रकाशित की गई. जिसे कार्यालयीन कामकाज के दिन ३० दिनों के लिए संकेत स्थल और एमबीएमसी मुख्यालय तथा सहायक संचालक, नगर रचना ठाणे, जिलाधिकारी कार्यालय इमारत की ३री मंजिल पर देखी जा सकती है. मीरा भायंदर शहर के विकास योजना प्रारूप (डीपी) की मुद्दत वर्ष २०१७ में पूर्ण हो चुकी है. इसके बाद से ही नई डीपी बनाने का कार्य चल रहा था और शहरवासियों को विगत ६ वर्षों से नए डीपी का इंतजार था. प्रथम दृष्ठि में ६७ पन्ने की बुधवार को प्रकाशित नए डीपी में

अधिकांश आपत्तियों पर संज्ञान लेकर उसमें फेरबदल किए जाने की बात सामने आई है. वहीं शहर के सघन मैंग्रोज बाधित क्षेत्र, बफर जोन और सीआरजेड बाधित क्षेत्रों में रहिवासी और इंडस्ट्रियल जोन दर्शाए जाने श्मशान के लिए आरक्षित भखंड को रहिवासी जोन में बदलने, वैद्यकीय सुविधा के बांधकाम क्षेत्र शैक्षणिक सुविधा, सार्वजनिक सुविधा के लिए आरक्षित भूखंड जैसे कई जनोपयोगी आरक्षण को रहिवासी क्षेत्र में बदलने आश्चर्य व्यक्त की जा रही है. २८ अक्टूबर २०२२ को प्रकाशित किया गया था. बता कि मीरा भायंदर शहर के विकास योजना प्रारूप को ठाणे नगर रचना व मूल्यांकन विभाग के सहायक संचालक किशोर पाटिल द्वारा तैयार कर २८ अक्टूबर २०२२ को प्रकाशित किया गया था. इस विकास योजना प्रारूप में कई त्रुटियां सामने आने के बाद इसे रद्द करने की मांग विधायक प्रताप सरनाईक, गीता जैन व पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने की थी. वहीं कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन पूर्व विधायक गिल्बर्ट मेंडोसा ने भी विकास योजना प्रारूप में कई सुधार करने के सुझाव दिए थे..

राशन की दुकानों पर फोर्टीफाइड चावल का वितरण

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : इन दिनों सरकारी राशन की दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को वितरित की जाने वाली कोटे की चावल को लेकर इसे प्लास्टिक का चावल होने, चीन का चावल होने जैसे तरह-तरह की अफवाहें फैल रही है। सोशल मीडिया पर भी इस चावल के बारे में भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं तो राशनिंग कार्यालयों में भी इस चावल के बारे में काफी लोगों ने शिकायते की है। जबकि सच्चाई यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव पर केंद्र सरकार ने लोगों में कुपोषण को दूर करने के लिए फोर्टीफाइड चावल तैयार की है। मिनिस्ट्री ऑफ क़ंज्यूमर्स अफेयर्स एंड फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्मेंट के १२ मई २०२३ के परिपत्र के अनुसार फोर्टीफाइड चावल में आयरन का प्रमाण ९०%, फोलिक एसिड ८०% व विटामिन बी १२ का प्रमाण ७०% है।देश और राज्य का कोई भी नागरिक और बालक कुपोषण का शिकार ना हो, इसलिए केंद्र व राज्य सरकार ने राशन की दुकानों पर फोर्टीफाइड चावल मिश्रित चावल की आपूर्ति की है। साधारण चावल में १% के अनुपात में मिश्रित किया गया है। जिसे राशन दुकानों से राशन कार्ड धारकों में वितरित की जा रही है। इस चावल से किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य को खतरा नहीं है।यह चावल पोषक और पौष्ठिक होने की वजह से उसे पकाते समय प्लास्टिक के समान दिखाई देता है, लेकिन इससे शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, ऐसी जानकारी राशनिंग अधिकारी राजेंद्र जाधव ने दी है।

केंद्र सरकार के परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर आपूर्ति की गई चावल ही लोगों में वितरित की जा रही है। यह चावल प्लास्टिक सदृश्य दिखाई दे रहा। इसके बावजूद यह स्वास्थ्य के लिए पोषक और स्वाथ्यवर्धक है। इस बारे में लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रम होने पर इस चावल के बारे में केंद्र सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए.

राशन में कोटे पर दी जाने वाली चावल को लेकर शुरू - शुरू में लोगों में काफी भ्रम था। लोग इसे प्लास्टिक की चावल समझ रहे थे, लेकिन यह फोर्टीफाइड मिश्रित चावल लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद और पौष्ठिक है। धीरे धीरे लोगों में फैला भ्रम अब दूर हो रहा है.

सोशल मीडिया के यू ट्यूब पर प्लास्टिक से चावल बनाने की वीडियो बहुत वायरल हुई थी। जिसे देखकर सरकारी राशन की दुकानों पर मिलने वाली चावल के बारे में संदेह और भ्रम की स्थिति थी, लेकिन इस चावल की सच्चाई जानने के बाद अब कोई शिकायत नहीं है -

शिवसेना शिंदे गुट के माजी नगरसेवक विक्रम प्रताप सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए जनकल्याण सेवा की संपादक सीमा गुप्ता.

जनसंख्या और वाहनों की वृद्धी के चलते यातायात नियमों में बदलाव

जेकेएस संवाददाता

भायंदर, मीरा-भायंदर मनपा और वसई- विरार मनपा क्षेत्र में यातायात की नई नीति लागू कर दी गई है. दोनों ही मनपाओं के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कर मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा यातायात की नई नीति लागू करने की रूपरेखा ५ अक्टूबर को जारी की गई थी. इस नई नीति की रूपरेखा पर सुझाव और आपत्ति दर्ज कराने के लिए दोनों मनपाओं के शहरवासियों को १५ दिन का समय दिया गया था. २० अक्टूबर को १५ दिन की समयावधि पूर्ण होने तक सिर्फ ७ लोगों ने यातायात की नई रूपरेखा पर अपने सुझाव और आपत्ति दर्ज कराएं हैं, जिसमें ५ सुझाव और २ आपत्ति का समावेश है. इसमें भी ६ सुझाव और आपत्ति भायंदर पश्चिम के उत्तन नाका, मीरारोड पूर्व के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल परिसर और शांतिनगर परिसर के संबंध में है. वहीं करीब २५ लाख की आबादी वाले वसई विरार क्षेत्र से सिर्फ १ आपत्ति दर्ज कराए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है.बता दें कि मीरा-भायंदर शहर में यातायात की नीति ठाणे ग्रामीण पुलिस द्वारा लागू की गई थी. शहर की जनसंख्या और वाहनों की संख्या की वृद्धि तथा शहर के विकास को देखते हुए उक्त नीति पुरानी हो गई थी, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था में दिक्कते और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी. इसको ध्यान में रखते हर मीरा भायंदर. वसई विरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर में यातायात की नई नीति निर्धारित की गई है. नई नीति निर्धारित करने से पूर्व मनपा प्रशासन के साथ मिलकर शहर के भीडभाड. वाले क्षेत्र, पार्किंग नो पार्किंग, सम-विषम पार्किंग, फेरीवाले क्षेत्र आदि का सर्वेक्षण किया गया हैनई यातायात नीति में मीरा-भायंदर तथा वसई- विरार महानगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत २७२ स्थानों पर पार्किंग व नो पार्किंग ९ मार्गों पर वन वे (एक दिशा मार्ग) का निर्णय लिया गया है, जिसमें मीरा भायंदर शहर में ५७. वसई में १०६ और विरार में १०९ स्थानों का समावेश है. भायंदर में ४ भागों तथा वसई में एक मार्ग पर भीडभाड.वाले समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है,

सरनाईक और विचारे में जुबानी हमले

जेकेएस संवाददाता

भायंदर। शिवसेना(शिंदे) विधायक प्रताप सरनाईक और शिवसेना (उद्धव) के सांसद राजन विचारे के बीच जुबानी हमले शुरू हो गए हैं।विचारे पर पलटवार करते हुए सरनाईक ने इशारों में कहा कि विचारे ने आज तक केंद्र या राज्य सरकार से एक पैसा भी मीरा भायंदर के विकास के लिए नही लाए हैं।मीरा भायंदर में विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार से मिली ३००० करोड.रुपए की निधि के बारे में जानकारी उन्हें नहीं थी तो प्रशासन से पूछ लेते,फिर मीडिया से बात करते। बीते दिनों पत्रकार परिषद में विचारे ने आरोप लगाया था मीरा भायंदर में सीसी रोड के लिए मंजूर १८०० करोड.में से सिर्फ ३८४ करोड रुपए कागजों पर मिले हैं।मनपा को ५५० करोड रुपए का कर्ज भी नहीं मिल रहा है।सोमवार को पत्रकार परिषद में बोलते हुए सरनाईक ने उनका जवाब दिया।कहा कि राज्य सरकार ने मीरा भायंदर में विकास योजनाओं के लिए ३००० करोड रुपए से अधिक की निधि मंजूर की है।१८०० करोड रुपए में से १४०० करोड.रुपए लागत के विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी कर कार्य आदेश भी जारी कर दिए गए है।और एक सप्ताह में काम भी शुरू होने जा रहे हैं। सरनाईक ने बताया कि निविदा प्रक्रिया,ठेका व कार्यदेश देने आदि सारे काम एमएमआरडीए ही करेगा।जबकि काम मनपा अधिकारियों के देखरेख में पूरे होंगे।सरनाईक ने विचारे का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि कुछ जानकारी तो रहती नही है,झूठे डींगे मारने आ जाते हैं।उन्होंने (विचारे)केंद्र या राज्य सरकार से आज तक एक भी पैसा नहीं लाया है। सरनाईक ने कहा कि मनपा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।इसे देखते हुए जो ४०० करोड.रूपया का कर्ज मनपा को लेना है, उसका भुगतान राज्य सरकार स्वयं करें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक-मुद्रक सीमा गुप्ता के लिए (प्रिंटींग) सागर प्रिंट एंड प्रोसेस, प्रगती इंडस्ट्रीयल, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००११ से मुद्रित १०१, १ला माला सेक्टर ११ सी-२८, टी.एम.टी. बस स्टॉप के पीछे, शांतिनगर, मीरारोड (पूर्व), जिला थाना ४०११०७ (महाराष्ट्र) से प्रकाशित संपादक - सीमा गुप्ता, सलाहकार : सुधाकर डी., पी.आर.बी अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चन के लिए उत्तरदायी है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र केवल जिला थाना रहेगा।
RNI NO. MAHHIN/2004/17839 Mob.No.9757262120 Email :newsjankalyanseva@gmail.com Jankalyan Seva GST No. 27AGUPG9011BIZI